भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 205

(जिसका उत्तर मंगलवार, 15 सितंबर, 2020/24 भाद्रपद, 1942 (शक) को दिया जाना है।)

गिरते सकल घरेलू उत्पाद में सुधार हेतु उपाय

205. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश की सकल घरेलू उत्पाद दर लगातार गिर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों की जीडीपी दर का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 2020 की तीसरी और चौथी तिमाही की अनुमानित जीडीपी कितनी है; और

(घ) जीडीपी दर को सुधारने के लिए किए गए सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (घ): राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी सकल घरेलू उत्पाद के अनुमानों के अनुसार 2014-19 में जीडीपी बढ़त औसतन 7.5 प्रतिशत थी जो कि जी-20 देशों में सर्वोच्च है। एनएसओ के ताजा अनुमानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान स्थिर (2011-12) मूल्यों पर वार्षिक जीडीपी बढ़त दरें क्रमश: 6.1 प्रतिशत (प्रथम संशोधित अनुमान) और 4.2 प्रतिशत (अनंतिम अनुमान) रहीं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा प्रकाशित अद्यतन जून 2020, विश्व आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूईओ) में अनुमानित आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी की वृद्धि दर में आई गिरावट 2018 में 3.6 प्रतिशत से 2019 में 2.9 प्रतिशत तक वैश्विक आउटपुट की वृद्धि में आई गिरावट के समान हो गई।

2019-20 की तीसरी तिमाही की समाप्ति की ओर खपत और निवेश बढ़ोतरी के संकेतों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में गति पुनः बहाल होनी आरंभ हो गई थी, लेकिन 2019-20 की चौथी तिमाही में कोविड-19 के प्रकोप से इसमें रुकावट उत्पन्न हुई। सरकार द्वारा 25 मार्च 2020 से 21 दिन का कड़ा देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया और विषाणु (वायरस) के विस्तार को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत तत्पश्चात इस लॉकडाउन का विस्तार किया गया तथा इसमें छूट दी गईं। भारत ने सबसे कठोर लॉकडाउन को लागू किया जैसाकि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा मापित सरकार अनुक्रिया कठोरता सूचकांक में परिलक्षित होता है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा 31 अगस्त 2020 को 2020-21 की पहली तिमाही के लिए जारी सकल घरेलू उत्पाद के अनुमानों के अनुसार, 2020-21 की पहली तिमाही के दौरान भारत में वास्तविक जीडीपी 23.9 प्रतिशत (2019-20 की पहली तिमाही में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में) तक संकुचित हो गई है। अप्रैल से जून की तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में संकुचन कठोर लॉकडाउन के प्रभाव के संगत है।

भारतीय अर्थव्यवस्था को 1 जून 2020 से चरणबद्ध तरीके से खोलने के साथ, उच्च आवृत्ति आर्थिक संसूचकों जैसे कि पीएमआई विनिर्माण, आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक, ई-वे बिलों, खरीफ फसल की बुवाई, विद्युत की खपत, रेल माल भाड़ा, माल परिवहन और यात्री वाहनों बिक्री बहाल हुई है और यह पिछले वर्ष की गतिविधियों के स्तरों की ओर बढ़ते अभिसरण को दर्शाता है।

सरकार ने निवेश एवं वृद्धि को बल प्रदान करने के लिए हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण ढांचागत सुधार किए हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तीय प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता (आईबीसी), अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को आसान बनाने के लिए माल एवं सेवा कर (जीएसटी), घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए मेक-इन-इंडिया कार्यक्रम, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) का उदारीकरण एवं जनधन-आधार मोबाइल (जेएएम) आदि शामिल हैं ताकि और अधिक पारदर्शिता, प्रभाविता एवं वित्तीय समावेशिता को बढ़ावा दिया जा सके। सितंबर, 2019 में नई घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए कारपोरेट कर की दर घटाकर 15 प्रतिशत कर दी गई है, जो विश्व में न्यूनतम है। दिसंबर 2019 में, सरकार ने 103 लाख करोड़ रुपये की राशि से नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइप लाईन की घोषणा की है जिससे अवसंरचना को पर्याप्त बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था को भी गति प्राप्त होगी। केंद्रीय बजट 2020-21 में भी व्यापक-आधारित तथा समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की गई है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, घरेलू मांग के समर्थन हेतु वैयक्तिक आय-कर को तर्कसंगत बनाना, कृषि क्षेत्र के समग्र विकास हेतु 16 मद की कार्य-योजना तथा अवसंरचना एवं ग्रामीण व्यय हेतु महत्वपूर्ण उपाय करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, मई 2020 में, सरकार ने भारत में कोविड-19 महामारी के प्रभाव से निपटने के लिए भारत की जीडीपी के 10 प्रतिशत के समतुल्य-20 लाख करोड़ रुपये के एक विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज में अन्य के अलावा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत राहत उपाय, एमएसएमई और एनबीएफसी हेतु राहत उपाय, मनरेगा के तहत बढ़ा आवंटन, मुद्रा ऋणों हेतु ब्याज आर्थिक सहायता और सामाजिक अवसंरचना हेतु व्यवहार्यता अंतराल निधियन स्कीम का पुनरूत्थान शामिल है। पैकेज के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा और निगरानी की जाती है।

*****